International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 04(II), October - December, 2024, pp. 138-141

थानागाजी तहसील में ग्रामीण विकास में कृषि की भूमिका

विनीता शर्मा*

प्रस्तावना

यहां हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं। गाँव का उदय, इतिहास में कृषि अर्थव्यवस्था के उदय के साथ जुड़ा है। हाल के आवष्किार के कारण ही मनुष्य स्थायी रूप से कृषि का विकास कर पाया जो कि खाद्यान्न की व्यवस्था का मूल स्रोत है। ग्रामीण विकास आमतौर पर अपेक्षाकृत पृथक व कम आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगो की आर्थिक खुशहाली से संबद्ध जीवन स्तर में सुधार की प्रक्रिया को दर्शाता है। कुछ विद्वानों ने ग्रामीण विकास की निम्न परिभाषाऐं दी हैंः– ग्रामीण विकास को शाब्दिक रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्र का चहुंमुखी विकास , ऐसा विकास जिससे वहाँ की जनता का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हा सके। विश्व बैंक के अनुसार वह व्यूह रचना जिससे ग्रामीण जनता का सामाजिक व आर्थिक विकास हो ग्रामीण विकास कहलाता है। '' रॉबर्ट चेम्बर्स के अनुसार ग्रामीण विकास वह पद्धति है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन और गरीब लोगो की सहायता की जाती है। जिससे अधिक लाभों की पूर्ति और नियंत्रण से ग्रामीण विकास हो सके। लघु कृषक, सीमांत कृषक, खेतीहर मजदूर और श्रमिक वर्ग के लोग इसमें शामिल किये जाते हैं ''।

ग्रामीण विकास की अवधारणा

ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्रपात महात्मा गाँधी जी के कथन '' भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, जब तक गाँवों का विकास नहीं होगा तथा गाँव पुनः आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता । ''

रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार ग्रामीण विकास एक ऐसा प्रयास है जो गाँव की संस्कृति को बरकरार रखते हुए आधुनिक संसाधनों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, भौतिक एवं नैतिक उत्थान में सहयोग दें।

यद्यपि भारत की जनगणना विभाग ने गांव को परिभाषित नहीं किया परन्तु उपर्युक्त शहरी क्षेत्र के मापदण्डों के आधार पर ग्राम को परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात वह क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या 5000 से कम हो एवं लोगो का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन हो तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो तथा वहाँ पर कोई भी अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, केन्टोमेन्ट बोर्ड न हो उसे ग्रामीण क्षेत्र कहा जा सकता है।

* शोधार्थी, भूगोल विभाग, निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान।

आजादी के 70 वर्ष बाद भी हमारे देश की ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ हे। ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में गांधीजी की अवधारणा को ध्यान में रखकर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई परन्तु इसके बाद में पं. जवाहर लाल नेहरू ने औद्योगिक विकास पर बल दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना अप्रेल 1981– 31 मार्च 1960 तक कृषि उत्पादन आशानुरूप नहीं बढने पर हरित क्रान्ति कार्यक्रम लागू किया गया जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969–74 में कृषि एवं पुनः सर्वोच्चता प्रदान की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974–78 रोजगार उद्योगो को गरीबी उन्मूलन और न्याय पर रखी गई थी। इस योजना में कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने गरीबी हटाओं का नारा देकर ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। महान सर्वोदयी विचारक श्री जयप्रकाश नारायण के क्रान्ति के आह्वान ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण विकास की अवधारणा पर बल दिया। इसी प्रकार राजीव गाँधी कू कार्यकाल में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर विशेष बल दिया गया। लेकिन वास्तविक रूप से जनता को इनका उचित लाभ नहीं मिला। यही कारण है कि आजादी से 70 वर्ष बाद भी बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

ग्रामीण विकास एवं नियोजन

प्राचीन समय से ही बाम राजनीतिक व्यवस्था में आधारभूत ईकाई रहे हैं। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी बोला जाता था। ग्राम एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र इकाई होते थे। भारत एक कृषि प्रधान देश है इसकी प्राचीन सुदृढ परम्पराऐं व इतिहास एवं जटिल सामाजिक व्यवस्था के कारण ग्रामीण विकास की नीतियों, क्रियायों और कार्यक्रमों को सही दिशा एवं सही आकार देने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास की बेहतर संभावना उसी स्थिति में हो सकती हैं जब ग्रामीण विकास की योजनाऐं सुनियोजित ढंग से चलाई जायें तथा योजनाओं को विकेन्द्रीकरण किया जाये। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ऊर्जा आपूर्ति, स्वच्छता, आवास आदि स्थिति में सुधार हो।

ग्रामीण विकास में कृषि की भूमिका

कृषि की व्युतपत्ति कृश धातु + इक् प्रत्यय से है। कृष का अर्थ कर्षण या खींचने से हैं। इक प्रत्यय से इसका अर्थ उस विशिष्ट प्रक्रिया से होता है जिसमें कर्षण या हल चलाना अथवा खेती करना सम्मिलित है। कृषि के अंग्रेजी समानार्थी श ।हतपबनसजनतम श्शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द गर ; ।हमतए ।हतपपिमसे वत ैवपसद्ध तथा कल्चर ;ब्नसजनतम दृ जैम बंतम ि्जतपससपदहद्ध से है। इस प्रकार फसलोत्पादन कृषि का प्रमुख कार्य है। अर्थात भूमि को जोतकर फसल पैदा करना ही कृषि है। इस अर्थ में कृषि का सीमित स्वरूप ही स्पष्ट होता है। बुकानन (1959) ने कृषि शब्द को मिश्र–शब्द पोर्टमाण्टयू कहा है। उनके अनुसार कृषि के अन्तर्गत मानव उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ या कच्चा माल उत्पन्न करने के लिए मृदा के उपयोग की अत्यन्त साधार प्रक्रिया से लेकर अत्यन्त संश्लिष्ट प्रविधियाँ सम्मिलित हैं।

भारत वर्ष की अधिकांश जनसंख्या गाँवो में निवास करती है। यदि हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो निश्चित ही हमें ग्रामीण विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा,तब तक भारतवर्ष का समग्र विकास संभव नहीं है। यह तभी सम्भव है जब सरकार कृषि क्षेत्र के विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगी। कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के बिना देश के विकास की कल्पना करना ही व्यर्थ है। विकास की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है। भारत में केन्द्र व राज्य सरकारों ने एक समान सतत् विकास प्रक्रिया को न अपनाकर भेद पूर्ण अर्थात् असंतुलित विकास प्रक्रिया को अपनाया है। इनकी नीतियों में क्षेत्रवाद, भाशावाद, जातिवाद, वोट बैंक की राजनीति की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। इस प्रकार विकास के क्षेत्र में विशमता अधिक दिखाई देती है। विकास प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करने के लिये जिम्मेदार होते है।

विकास प्रक्रिया के प्रत्येक क्षेत्र में वित्त की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कृषि क्षेत्र के विकास एवं ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में वित्तीय संसाधनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में सरकारों ने भी गंभीरतापूर्वक विचार करना शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों में के प्रवाह को बढाने की प्रक्रिया शुरू की है। आज ग्रामीण क्षेत्रों भूमि में बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। कृषि क्रियाओं जी को सम्पन्न करने के लिए सुविधापूर्वक वित्त उपलब्ध कराने विशेष प्रयास यि जा रहे हैं। इस प्रकार धन के अभाव में कृषि महा कार्यो में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने पाये इसके प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के साथ–साथ पंचवर्षीय योजनाओं में भी ग्रामीण विकास को फोकस किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके समर्थन में सरकारी एजेन्सियों के साथ बैंकिंग क्षेत्र को विस्तार प्रदान किया जा रहा है। इन प्रयासों के कारण ही देश के ग्रामीण विकास हु संस्थागत साख की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी सामान्य अवधारणा यह है कि संस्थागत साख में हुई वृद्धि, बढे हुए कृषि उत्पादन, उत्पादकता तथा ग्रामीण आय से सामंजस्य नहीं रखती है। यह की प्रमुख रूप से विकास के लिए आवश्यक प्रभावी क्षेत्रीय अथवा स्थानीय साख योजनाओं की अनुपस्थिति के कारण देखने को मिलती है। हमें संतुलित विकास की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। संतुलित विकास का तर्क हमारे सभी अर्थशास्त्रियों की ओर से भी दिया गया है। संतुलित विकास के समर्थक ग्रामीण विकास को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में लघु एवं कुटीर उद्योगो की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना ग्रामीण विकास को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कृषि विकास के साथ–साथ कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगो पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित करना होगा।

आज कृषि क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण विकास की कल्पना को साकार किया जा सकता है। कृषि को भी एक उद्योग का दर्जा प्रदान करके उद्योगों जैसी सुविधाऐं प्रदान करने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में नगदी फसलों ;बै ब्तवचेद्ध को उगाने का प्रचलन बढा है। इस प्रकार की फसलों को बेचकर कम समय में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। आज कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में निरन्तर प्रगति हो रही है। कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास में सीधा सम्बन्ध है। इसलिए नीति निर्माताओं को कृषि क्षेत्र की प्रगति की ओर ध्यान देना होगा तभी ग्रामीण विकास की कल्पना साकार हो पायेगी। आज इस ओर बहुत ही तीव्र गति से प्रयास किये जा रहे हैं जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है।

ग्रामीण विकास में कृषि की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। आज ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन के साधनों के विस्तार से भी इस क्षेत्र ने प्रगति की है। कृषि क्षेत्र के विकास भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है।

आज ग्रामीण क्षेत्रमें कृषकों के जीवन स्तर में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के कारण जीवन स्तर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए है। आज कृषि क्षेत्र के विकास में संस्थागत वित्त की उपलब्धता ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास की इस राह को सुगम बना दिया है। ग्रामीण विकास में वित्तीय संसाधनों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती जा रही है।

आज हमारी वार्षिक योजनाओं के साथ–साथ पंचवर्षीय योजनाओं में भी ग्रामीण विकास को फोकस किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके समर्थन मेंसरकारी एजेन्सियों के साथ बैंकिग के क्षेत्र को विस्तार प्रदान किया जा रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप देश के ग्रामीण विकास हेतु संस्थागत साख की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी सामान्य अवधारणा तथा संस्थागत साख में वृद्धि बढे हुए कृषि उत्पादन रूप उत्पादकता तथा ग्रामीण आय से सामंजस्य नहीं रखती है। यह कमी प्रमुख रूप से विकास के लिए आवश्यक प्रभावी क्षेत्रीय अथवा स्थानीय साख योजनाओं की अनुपस्थिति के कारण देखने को मिलती है। हमें संतुलित विकास की तरफ अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। संतुलित विकास का तर्क हमारे भी अधिकांश अर्थशास्त्रियों की ओर से दिया गया है। संतुलित विकास के समर्थक इसलिए इसे एक दूसरे का पूरक मानते ही है। ग्रामीण विकास के संदर्भ में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। इसे नकारा नहीं जा सकता है लेकिन विभिन्न कृषि यंत्रों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी लोगो की समस्या का बहुत विकराल रूप है।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने में सार्थक प्रयास करने होंगे इस कार्य में कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगो की भूमिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त दान बेरोजगारी को लघु एवं कुटीर उद्योगो की स्थापना करके दूर किया जा सकता है।

ग्रामीण विकास को वर्तमान परिस्थितियों की विभिन्न कारक प्रंभावित करते हैं। इन कारकों में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं जनसंख्या है। वृद्धि प्रमुख रूप से है, वैसे यह भी कहा जाता है कि ग्रामीण विकास में बढती जनसंख्या एक महत्वपूर्ण भूमिका कृषि निभा रही है जनसंख्या श्रमपूर्ति का स्त्रोत है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर घटती हुई जोत और संस्थागत स्त्रोतो से उपलब्ध तीव्र वित्त की कमी ने विकास प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावित की पर्याप्ता होने पर भी अर्थ व्यवस्था में उपलब्ध साधनों एवं श्रम शक्ति का कुशलता पूर्वक प्रयोग करके विकास प्रक्रिया को आगे बढाया जा सकता है। ग्रामीण विकास के लिए आर्थिक गौर गैरआर्थिक दोनो ही तत्व आवश्यक है। प्रो.रेगनार का भी यह मत है कि आर्थिक विकास का मानवीय मूल्यों, सामाजिक प्रवृत्तियों, राजनीतिक दशाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। '' न्छण्व् (संयुक्त राष्ट्र संघ) मे प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार एक उपयुक्त वातावरण की अनुपस्थिति में आर्थिक प्रगति असंभव है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि लोगो में प्रगति की प्रबल इच्छा हो, वे उसके लिए हर सम्भव त्याग करने को तत्पर हों वे अपने आपको नये विचारों के अनुकूल ढालने को जागरूक हों और उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व वैधानिक संस्थाऐं इन इच्छाओं को कार्यक्रम में परिणित करने में सहायक हों।

आज ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्धित विकास, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के समक्ष प्रमुख कार्यो में से एक है। केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम, देश के समग्र विकास में गाँवों के महत्व को दर्शाता है और उन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु प्रतिबद्ध हैं। जो विगत में विभिन्न कारणों से शहरी क्षेत्रों से पिछड़ गये हैं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास में कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कृषि, अर्थशास्त्र– पी.के. गुप्ता, वृंदा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था– मिश्र एवं पुरी, हिमालया प्रकाशन।
3. भारत की दशाऐं – अर्मत्यसेन
4. भारतीय कृषि (समस्याऐं, विकास एवं सम्भावनाऐं– डां. बद्री विशाल त्रिपाठी, किताब महल एजेन्सीज, इलाहाबाद। भारत की आर्थिक समस्याऐं मामोरिया एवं जैन।
5. कृषि भूगोल– डॉ. जे.एन. पाण्डेय एवं डॉ. एस.आर. कमलेश
6. दैनिक समाचार पत्र– अमर उजाला, दैनिक जागरण।
7. एकीकृत जिला आयोजन– आयोग, भारत सरकार, हिन्दुस्तान।
8. योजना पत्रिका, कुरूक्षेत्र पत्रिका।

❖◆❖